

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

अवकाश सूचना

समाचार पचीसा के कार्यालय में 11 जून रविवार अवकाश रहेगा। समाचार पचीसा का अगला अंक 13 जून मंगलवार को प्रकाशित होगा।

दीदी के लोकतंत्र पर दलों को नहीं भरोसा

बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन भी हिंसा जारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन भी हिंसा जारी थी। विपक्षी पार्टियां भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई(एम) ने आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवारों को सत्तारूढ़ टीएमसी कार्यकर्ताओं और गुंडों द्वारा पर्चा जमा करने से रोका जा रहा है।



सत्तारूढ़ और विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा के मामले बांकुड़ा, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर, वर्धमान और मुर्शिदाबाद जिलों में देखने को मिली। नामांकन के पहले दिन हिंसा के दौरान शुरुवार को एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। हत्या के बाद कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, 90% हमने सभी घटनाओं की रिपोर्ट मांगी है और पुलिस को जरूरी निर्देश दिए गए हैं।

भाजपा ने पंचायत चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती की मांग की। इस पर सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि विपक्ष हार के डर से बहाने ढूंढ रही है। डेमोकल में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के पास से पिस्तौल बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुर्शिदाबाद के

डोमकोल में विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के गुंडे आमनेयास्रों के साथ बीडीओ के दफ्तर के सामने घूम रहे थे। क्षेत्र में अशांति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के साथ नागरिक स्वयंसेवकों को लाठियों के साथ देखा गया है।

बोरभूम जिले के लाभपुर में भाजपा उम्मीदवारों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया। बांकुड़ा के विष्णुपुर से भी ऐसी घटनाएं होने की सूचना मिली है, जहां सीपीआईएम उम्मीदवारों ने टीएमसी पर नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा-हमें केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती की मांग की है। लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक हमारी दलीलों नहीं सुनी हैं। उन्होंने कहा- पुलिस की वर्दी

पहने नागरिक स्वयंसेवकों को अब नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। इससे सत्तारूढ़ दल के उपद्रवियों को खुली छूट मिल रही है। यह कानून का घोर उल्लंघन है। टीएमसी के अध्यक्ष सदस्य और पार्टी प्रवक्ता शान्तु सेन ने कहा- बंगाल की जनता टीएमसी के साथ है भाजपा या कांग्रेस या सीपीआई(एम) के साथ नहीं। अगर विपक्ष चाहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ से पंचायत चुनाव में शांति सेना की तैनाती की मांग कर सकता है।

राजनीतिक दलों की मांग, पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की हो तैनाती

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को एक चिट्ठी लिख कर मांग की है कि पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कराई जाए, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। कांग्रेस सांसद ने टीएमसी पर खून की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुर्शिदाबाद के खारग्राम में एक सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी। यह पंचायत चुनाव के मद्देनजर ही हुआ। जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप था, उसे खारग्राम प्रशासन की ओर से सुरक्षा मिली थी, जिसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

अधीर रंजन की चिट्ठी में क्या?

कांग्रेस सांसद ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें कहा गया है कि मौजूदा समय में बंगाल में जंगलराज चल रहा है, जिसमें सत्तारीन पार्टी के कार्यकर्ता विपक्षी कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे हैं। राज्य के हर गली-गुच्छ में अव्यवस्था का राज है। लोकतंत्र के आदर्शों को सत्ता पर

काबिज पार्टी द्वारा कब्र में दफना दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हमें डर है कि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करना एक दूर की कौड़ी ही रह जाएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन चुनावों को केंद्रीय सुरक्षाबलों की निगरानी में कराया जाए। इस मामले में आपकी ओर से कदम उठाया जाना अपेक्षित है।

भाजपा नेता की चिट्ठी में क्या?

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और सांसद, डॉ सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए आगामी पंचायत चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात भी की।

सुकांत मजूमदार ने लगाया आरोप

सुकांत मजूमदार ने कहा कि कल एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने सवाल किया कि अगर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बरकरार है, तो चुनाव नजदीक आने पर हत्याएं क्यों होती हैं? हमने पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए राज्यपाल से अनुरोध किया है।

जल जीवन मिशन से बचाई जा सकती हैं चार लाख जिंदगियां

नई दिल्ली। अगर जल जीवन मिशन (जेजेएम) सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य को पूरा करता है तो डायरिया से होने वाली लगभग चार लाख लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। दिल्ली में शुरुवार को भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉ. रोडरिको एच. आफ्रिन की ओर से जारी अध्ययन की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। आफ्रिन भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि हैं। जेजेएम योजना के तहत 2024 तक देश के सभी साढ़े छह लाख गांवों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

डब्ल्यूएचओ के अध्ययन के अनुसार, जल जीवन मिशन से हर घर नल होने से जल जनित बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है और गुणवत्तापूर्ण जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। देश में जल जनित बीमारियां मौतों का बड़ा कारण हैं। सुरक्षित पेयजल से जल जनित रोगों बीमारियों से बचाव होगा। इससे हर साल लगभग 4 लाख डायरिया रोग से होने वाली मौतें रुकेंगी। भारत में 5 साल तक के बच्चों की मौतों का तीसरा बड़ा कारण डायरिया है और यह 13 फीसदी मौतों की वजह भी बनता है। लिहाजा इससे निपटने के लिए देश को दीर्घकालीन प्रयासों की जरूरत है।

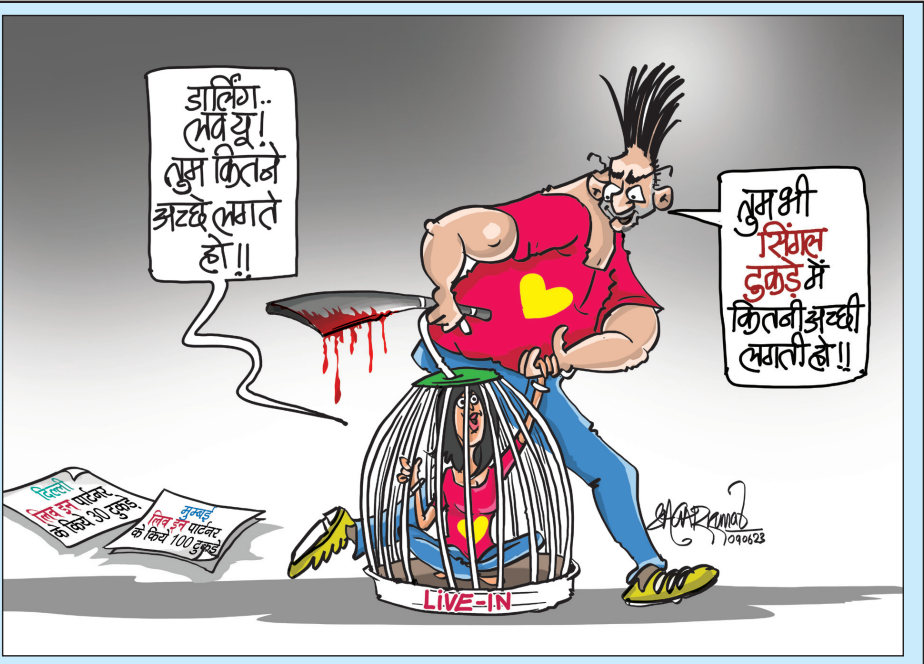
डब्ल्यूएचओ के अध्ययन में सामने आई जानकारी

जल जीवन मिशन का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य राज्यों के उन ग्रामीण इलाकों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है, जहां बढ़ती जनसंख्या के साथ पानी जैसी समस्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां लोगो को कई किलोमीटर दूर पैदल चल कर पानी लाना पड़ता है।

10 हजार करोड़ की होगी बचत

जेजेएम योजना से करोड़ों लोगों को अतिसार रोग से बचाया जा सकेगा। इससे दस हजार करोड़ तक की बचत होगी। महिलाओं को लगने वाले हर दिन के समय में 6.66 करोड़ घंटों बचत होगी। 2018 में भारत की कुल आबादी के 36 फीसदी और ग्रामीण आबादी के 44 फीसदी लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की पहुंच नहीं थी। उन्हें गुणवत्तापूर्ण पानी के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है।



कम होगा श्वसन रोगों से मृत्यु का खतरा

नई दिल्ली। लोवर रिस्पैटोरी इन्फेक्शन (एलआरआई) दुनियाभर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में दुनियाभर में इसके कारण 2.38 मिलियन लोगों की मौत हुई। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अब इस मृत्युदर को काफी कम किया जा सकेगा। लगभग 60 वर्षों के प्रयास के बाद, घातक श्वसन संक्रमण रिस्पैटोरी सिंक्रिटियल वायरस या आरएसवी के लिए अब टीके उपलब्ध हैं। फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने अमेरिका में पिछले महीने जीएसके कंपनी की एरेक्सवी और फाइडर की एरिब्रोको वैक्सीन को मंजूरी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल इन दोनों वैक्सीन को 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए मंजूरी दी गई है। इस आयुवर्ग वालों में श्वसन संक्रमण के



कारण मौत का खतरा अधिक रहा है। वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि हमें उम्मीद है कि ये टीके गंभीर श्वसन रोगों और इसके कारण होने वाली मृत्युदर को कम करने में मददगार हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में आरएसवी वायरस के कारण ब्रॉन्कोलाइटिस (फेफड़ों में छोटे वायुमार्गों की सूजन) और निमोनिया (फेफड़ों का संक्रमण) का सबसे ज्यादा जोखिम देखा जाता रहा है। इसी माह 21

जून को सीडीसी की एक बैठक है जिसमें टीकों की उपलब्धता को लेकर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। नेशनल फाउंडेशन फॉर इंफेक्सियस डिजीज के मेडिकल डायरेक्टर विलियम शेफ़रन कहते हैं, ये टीके किसी वरदान से कम नहीं हैं। इससे हर साल होने वाली मृत्युदर में काफी कमी आने की उम्मीद है।

एरेक्सवी वैक्सीन असरदार

जीएसके (ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन) के टीके एरेक्सवी को मंजूरी मिलने से पहले इसे 60 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों पर सिंगल डोज वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण में 12,500 लोगों को एरेक्सवी और इतने ही लोगों को प्लेसिबो दिया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि ये

टीके आरएसवी वायरस के कारण होने वाले लोवर रिस्पैटोरी ट्रेक्ट डिजीज के जोखिम को 82.6% और गंभीर बीमारी होने के जोखिम को 94.1% तक कम कर सकते हैं।

एरिब्रोको वैक्सीन की प्रभाविकता

इसी प्रकार फाइजर के एरिब्रोको की भी नैदानिक परीक्षणों में कई प्रकार से लाभकारी पाया गया है। 17,000 लोगों पर वैक्सिनो और प्लेसिबो के साथ किए गए अध्ययन में इसके भी बेहतर परिणाम देखे गए। इन टीकों को दो या अधिक लक्षणों वाले लोवर रिस्पैटोरी ट्रेक्ट डिजीज पर 66.7% और तीन या अधिक लक्षणों पर 85.7% तक प्रभावी पाया गया। यह आरएसवी से जुड़े अक्यूट रिस्पैटोरी डिजीज के जोखिम को 62 प्रतिशत तक कम कर सकता है।

30 जून के बाद खुलेगा मनाली-किरतपुर फोरलेन : अनुराग
हमीरपुर। हिमाचल में बन रहे मनाली फोरलेन मार्ग किरतपुर नेशनल सेक्शन को 30 जून के बाद लोगों की सुविधा के लिए खोल दिया जाएगा। इसका ट्रायल चल रहा है। यह बात केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि उनसे आगे रेल लाइन के लिए हिमाचल सरकार का हिस्सा नहीं आ रहा है जिस कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। 1000 करोड़ आर्विंदत कर दिया गया है। 48 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण कर ली गई है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरह विपक्ष की बैठकें हो रही हैं विपक्ष एकता की दुहाई दे रहा है लेकिन वह बिहार के पुल की तरह धराशाय हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के बीच भाजपा अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएगी। राहुल गांधी को कोर्ट के फैसले के बाद सदस्यता से हटया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भर में सबसे लोकप्रिय हैं।

प्रमुख समाचार

कांग्रेस के लिए राजनीति व्यवसाय है: स्मृति ईरानी
अमेठी (उप्र)। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने "मुहब्बत की दुकान खोलने" संबंधी राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर शनिवार को हमला बोलाते हुए कहा कि कांग्रेस ने "दुकान खोलने की बात" शब्द का प्रयोग करके यह साबित कर दिया है कि उसके लिए राजनीति एक व्यवसाय है और राजनीति से उसका कोई लेना-देना नहीं है। गौतलब है कि इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान दिए गए अपने उन नारे का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह "नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे।" उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए यह भी कहा था कि "भारत समझ गया है कि जिस तरह की नफरत भाजपा समाज में फैला रही है, उससे वह आगे नहीं बढ़ सकता।" ईरानी ने 'मुहब्बत की दुकान' टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर पत्रकारों से कहा, कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता दुकान खोलने की बात कर रहे हैं।



केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ महारैली : आम आदमी पार्टी
नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ रविवार को यहां रामलीला मैदान में महारैली करेगी, जिसमें एक लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। पार्टी की एक प्रवक्ता ने यह दावा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ संसदीय अध्यक्ष, आतिशी और संजय सिंह सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। आप की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा कि रैली में एक लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। गुप्ता ने कहा, "हमने व्यापक अभियान चलाया है, लोगों से संपर्क कर उन्हें अध्यादेश के बारे में बताया है कि यह उनके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करेगा।" गुप्ता ने कहा, "दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को तीन बार चुना है।



8 साल की उम्र में हासिल किया 8 विश्व रिकॉर्ड
नई दिल्ली। आठ वर्ष की बच्चा है सोनीपत का रहने वाला मार्टिन, जिसने सिर्फ आठ वर्ष की उम्र में खस उपलब्धि हासिल की है। उसके पास आज आठ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। मार्टिन ने ये उपलब्धि क्रिक बॉक्सिंग में हासिल की है। पॉपिंग ब्रेड पर 3 मिनट में 918 पंच करने का रिकॉर्ड बनाया जा चुका है। इस रिकॉर्ड को रूस के 20 वर्षीय पावेल ने बनाया था मगर मार्टिन ने सिर्फ आठ वर्ष की छोटी उम्र में ही इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। मार्टिन ने तीन मिनट में 1700 बार पंच मारे और इस रिकॉर्ड को बनाया है। उसकी इस शानदार उपलब्धि और वर्ल्ड रिकॉर्ड को देखते हुए उसे लंदन के पार्लियामेंट से सम्मानित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान ही मार्टिन ने क्रिक बॉक्सिंग सिखना शुरू किया। उस समय मार्टिन की उम्र महज साढ़े छह साल की थी। उसने इस दौरान रोज इसकी प्रैक्टिस की।



हिन्दू धर्म में आस्था के चलते मुस्लिम युवक की जान संकट में
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले एक मुस्लिम युवक को अपने घर में देवी-देवताओं की मूर्तियां रखने के कारण जान के लाले पड़ गए हैं। उसे लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा मांगी है। मुस्लिम युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुद के सनातन धर्म अपनाने की गुहार लगाते हुए कहा है कि योगी जी मुझे सनातन धर्म में शामिल करा दीजिए। इन पापियों से मुझे बचा लीजिए। दरअसल जुनैद अपने घर में भगवान की प्रतिमाएं रखकर पूजापाठ करते हैं। इसके साथ ही भगवा वस्त्र पहनकर मंदिर जाते हैं। यह बात कुछ कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रही है। मामला कानपुर के बाबूपुरवा कोतवाली क्षेत्र स्थित खटिकाना में रहने वाले जुनैद के साथ जुड़ा हुआ है। जुनैद की मां रानी बेगम ने बताया कि जुनैद जब छोटा था, तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी।



सचिन के निर्णय को लेकर दौसा की श्रद्धांजलि सभा पर निगाहें टिकी

राहुल संपाल

किसानों के मसीहा के रूप में पहचाने जाने वाले दिवंगत कांग्रेस नेता राजेश पायलट की 11 जून को पुण्यतिथि है। इसी दिन हर साल दौसा के भडाणा गांव में एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है। लेकिन रविवार यानी कल होने वाली इस सभा पर हर किसी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि हर कोई यह जानना चाहता है कि सचिन पायलट अपनी पिता की पुण्यतिथि वाले दिन क्या अहम एलान करने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से प्रदेश की सियासत में सचिन पायलट के भविष्य को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। उनकी नई पार्टी बनाने की संभावित घोषणा को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक में बहस छिड़ी हुई है। हालांकि इन सभी पर पायलट ने चुप्पी साध रखी है। उधर, राजधानी दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान आश्वस्त है कि पायलट उनका साथ छोड़कर

कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में राजस्थान के लोगों यह जानने के लिए बेताब है कि आखिर 11 जून को सचिन क्या करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे राजेश पायलट के बेटे और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट पिछले साढ़े चार से कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह एक है कि प्रदेश में भाजपा शासन के दौरान विपक्षी दल के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए सचिन ने जी-जान लगाकर मेहनत की। कांग्रेस राज्य की सत्ता तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन उन्हें प्रदेश का सीएम नहीं बनाते हुए डिप्टी सीएम बना दिया गया है। खुद पायलट और उनके समर्थकों को पूरा विश्वास था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें ही मिलेगी। लेकिन ऐसा



नहीं हुआ इसके बाद से लगातार पायलट प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर कई बार हाईकमान को अपने बगावती तेवर दिखा चुके हैं। लेकिन हाईकमान ने कोई कदम नहीं उठाया। यहीं नहीं सीएम गहलोत और पायलट के बीच आए दिन जुवाबी जंग भी देखने को मिलती है। हाल ही में विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए दिल्ली दरबार ने एक बार फिर दोनों के बीच सुलह होने का दावा किया है। लेकिन आज तक सचिन की उठाई मांगों पर न तो कांग्रेस हाईकमान ने कोई फैसला लिया है न ही प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने। यही कारण है कि पिता की पुण्यतिथि वाले दिन पायलट क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार संदीप दहिया कहते हैं

कि पायलट के पिता राजेश पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर 11 जून को दौसा में हर साल कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में हर साल करीब 3000 लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस बार का कार्यक्रम सचिन पायलट के पार्टी के खिलाफ बगावती तेवरों के चलते चर्चा में है। संभावना है कि इस कार्यक्रम में 5 से 7 हजार लोग शामिल हों। क्योंकि पायलट के समर्थक जो इस विधानसभा चुनाव में टिकट चाहते हैं, वह भी चुनावी साल में अपने नेता के सामने अपनी ताकत का अहसास कराने से नहीं चुकेंगे। यहीं नहीं 11 तारीख पायलट के लिए काफी अहम है। बीते दिनों के कई कार्यक्रमों पर अगर नजर डालें, तो सामने आएगा कि हर बड़ा आंदोलन पायलट ने 11 तारीख से ही शुरू किया है। 11 जून के कार्यक्रम की रूपरेखा वे 11 अप्रैल से ही तैयार कर रहे थे। यही वजह है कि 11 मई को उन्होंने यात्रा निकाली। लेकिन अगर रविवार को कोई वैकेंड फैसला नहीं लेते, तो फिर यह बात साफ

इसलिए महत्वपूर्ण है 11 का आंकड़ा

तीन साल पहले 11 जून 2020 को सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत का निर्णय लिया था। इसी दिन बगावत करना तय था, लेकिन इसकी भनक गहलोत गुट को लग गई थी। ऐसे में ठीक एक महीने बाद 11 जुलाई सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायक राजस्थान की सीमा से बाहर गुमनाम स्थान पर चले गए। अगले दिन पता चला कि सचिन पायलट गुट के नेता राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते हुए मानेसर होटल में पहुंच गए। गहलोत सरकार गिरने की कगार पर आ गई थी। उधर, सीएम गहलोत को भी सरकार बचाने के लिए विधायकों की बाड़ेबंदी करनी पड़ी।

खड़गो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर : भाजपा

बंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा और राज्य के तीन अन्य भाजपा सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गो को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए भाजपा नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गो पर उनके ओडिशा ट्रेन दुर्घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र पर पलटवार किया है। भाजपा नेताओं ने खड़गो के पत्र को उच्च बयानबाजी और कम तथ्य वाला बताया और कहा कि मैसूर में कोई टकराव नहीं था जिस कि आपके पत्र में कहा गया है। आपके कद के नेता को यह शोभा नहीं देता कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिले तथ्यों के आधार पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखें। भाजपा नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में, आपको फेक न्यूज की तथ्यों के रूप में फिर से गढ़ने के लिए मजबूर किया। गौड़ा के अलावा, पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में सांसद तेजस्वी सूर्या, पीसी मोहन और एस मुनिस्वामी शामिल हैं।

सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल होंगे एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष

मुंबई। एनसीपी सुप्रियो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया है। इसकी घोषणा खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की और सुप्रिया सुले को हरियाणा और पंजाब की जिम्मेदारी भी दी गई है। पवार ने 1999 में उनके और पीए संगमा द्वारा स्थापित पार्टी को 25वीं वर्षगांठ पर यह घोषणा की। यह घोषणा शरद पवार के भतीजे और राकोंपा के एक प्रमुख नेता अजीत पवार की उपस्थिति में की गई थी। सुप्रिया सुले को जहां महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला युवा और लोकसभा समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं प्रफुल्ल पटेल मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की कमान संभालेंगे। पिछले महीने, अनुभवो राजनता शरद पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना इस्तीफा वापस ले लिया था क्योंकि भावनात्मक पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और उनके फैसले का विरोध किया।

पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होगी बसपा

लखनऊ। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राजद, जदयू, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी समेत कई दलों के शीर्ष नेता भाग लेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इस बैठक में रणनीति तय होगी। विपक्षी एकता के जरिए भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल की है। लेकिन बसपा इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। पटना में 23 जून को आयोजित होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में बसपा हिस्सा नहीं लेगी। बसपा की ओर से कोई भी नेता इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बसपा आगामी लोकसभा चुनाव महागठबंधन के साथ नहीं लड़ेगी बल्कि बिहार की सभी 40 सीटों पर बसपा अपना उम्मीदवार उतारोगी। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने ये जानकारी दी है। भाजपा को हराने के लिए अब विपक्षी दलें अलग-अलग चुनाव लड़ने के बजाय एकसाथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।

कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर टीएमसी पर भड़के अधीर रंजन

कोलकाता। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारी आशंका सच साबित हो रही है। उन्होंने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में सत्ताधारी दल गुंडागर्दी कर रहा है और डर का माहौल बनाने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनियोजित तरीके से विपक्ष को डराया जा रहा है, वे (टीएमसी) नहीं चाहते कि मुर्शिदाबाद चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो। चुनाव प्रचार के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद यह मामला सामने आया है। एक पार्टी कार्यकर्ता फूलचंद शेख की हत्या के बारे में बात करते हुए, चौधरी ने आरोप लगाया कि राज्य में जंगल राज कायम है, जिसके तहत सत्तारूढ़ दल के गुंडे और बदमाश विपक्षी कार्यकर्ताओं को शिकार बना रहे हैं, जैसे वे कुछ गहरे राक्षस हैं। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद के खरामा में एक सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। यह पंचायत चुनाव के मद्देनजर हुआ।

गिरिराज सिंह पर गोडसे वाले बयान पर हमलावर हुए सिब्लल

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत बताया था और कहा था कि वह मुगल शासक बाबर और औरंगजेब की तरह आक्रमणकारी नहीं था क्योंकि वह भारत में पैदा हुआ था। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्लल ने गिरिराज सिंह के गोडसे पर दिए इस बयान को लेकर शनिवार को उत्तर हमला बोला। उन्होंने कहा, इसका मतलब जो भी हिन्दुस्तानी यहां पैदा हुआ है वो कल्ल करता है तो वो भारत का सपूत है। सपूत का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अच्छा पुत्र हुआ। तो क्या गिरिराज सिंह के हिसाब से गोडसे अच्छे पुत्र थे? संविधान की एक कैबिनेट जिम्मेदारी होती है, इसका मतलब है कि गिरिराज सरकार के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या मोदी और अमित शाह भी इस बात से सहमत हैं, उन्हें इसका खंडन करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि ये बयान बेबुनियाद है और गिरिराज ने जो कहा है वो गलत है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल की अमेरिका यात्रा पर साधा निशाना

विदेश जाकर अपने देश की बुराई करना शोभा नहीं देता

गांधीनगर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका गए हुए थे। वहां उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया था। इतना ही नहीं उन्होंने यह तक कह डाला था कि मोदी भगवान को भी बता सकते हैं कि क्या करना है। इस पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा किसी भी नेता को शोभा नहीं देता कि वह विदेश में जाकर अपने देश को नीचा दिखाए। राहुल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। वह भारत का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हर विदेश यात्रा में वह अपनी गलतियों को दोहराते हैं।

केंद्रीय मंत्री गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर कस्बे में मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार की राहुल गांधी द्वारा की गई आलोचना का जिक्र किया। उन्होंने राहुल को अपने पूर्वजों से सीख लेने की सलाह दी।

शाह ने कहा कि किसी भी देशभक्त



व्यक्ति को भारत के भीतर देश की राजनीति पर चर्चा करनी चाहिए न कि विदेश जाकर। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के नेता को विदेश जाकर देश की राजनीति पर चर्चा करना और देश की निंदा करना शोभा नहीं देता है। उन्होंने लोगों से कहा कि इस राहुल बाबा को याद रखें। वहाँ, मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने पर शाह ने कहा कि इस अवधि में देश ने कई बड़े बदलाव देखे हैं। लेकिन कांग्रेस भारत विरोधी बातें करना बंद नहीं करती है। राहुल बाबा गर्मी की वजह से छुट्टी पर विदेश जा रहे हैं। वह विदेशों में देश की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को अपने पूर्वजों से सीख लेने की सलाह देना चाहूंगा।

राहुल को विदेश में अल्पसंख्यक याद आते हैं: हरदीप पुरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए जा रहे बयान को लेकर उत्तर निशाना साधा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये (राहुल गांधी) विदेश जाते हैं तो इनको अल्पसंख्यक याद आ जाते हैं, जब आप 14 साल के थे तब हमारे 3,000 सिख भाइयों की हत्या हुई थी। आप कोई भी बयान दे देते हो और जब उसके बाद आपका झूठ पकड़ा जाता है तो माफी मांगते हो। उन्होंने राफेल का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये सब क्या है? आज का समय विश्वासनीयता का है। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने 220 करोड़ वैक्सीन ना केवल बनाई हैं बल्कि उनको सही से वितरित भी किया है। पुरी ने कहा कि 100 देशों को तो हमने सीधे तौर पर वैक्सीन दी है। नीति-नीयत और नेता अगर ये तीनों इनके हैं तो सब ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल ने सही मायने में विकास और समृद्धि सुनिश्चित की है। बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर लोगों के जीवन को आसान बनाने तक, न्यू इंडिया ने एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, उज्वला, अमृत जैसी कुछ योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यूपीए सरकार के वर्षों में राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया कुल मिलाकर निष्क्रियता और नीति-पक्षाघात की विशेषता थी। उस समय देश में विकास पर कोई ध्यान नहीं था और भारत फ्रेंडाइल-फाइव अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। उन्होंने दावा किया कि मोदी जी के नेतृत्व में, भारत ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।

संबंधित राज्य की सरकार के बीच तालमेल, सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार, आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर रिपोर्ट भी मांगी है। सभी से चुनाव में जीत के लिए इन्वोवेटिव आईडिया मांगे गए हैं। इसके अलावा राज्य प्रभारियों से सरकार और संगठन के बीच आ रही दिक्कों के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। सांसदों और विधायकों के कामकाज को लेकर भी चर्चा होगी।

भाजपा नेता ने आगे बताया कि राज्य सरकार की केंद्र और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व

के साथ तालमेल को लेकर भी चर्चा होगी। इसमें भाजपा शासित राज्यों के उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल भी मांगी गई है, जिन्हें केंद्र सरकार से मंजूरी मिलनी है। ताकि, लोकसभा चुनाव से पहले विकास के मुद्दे पर कहीं से भी पार्टी को मुंह की न खानी पड़े। तालमेल बेहतर करके भाजपा राज्यों में अपना पकड़ और और मजबूत बनाया चाहती है। अभी 10 राज्य ऐसे हैं, जहां भाजपा के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा पांच राज्यों में भाजपा गठबंधन की सरकार है।

अध्यादेश के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल से किया सवाल

जब धारा 370 हटाई गई तो कहां थे?

श्रीनगर। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ शनिवार को अरविंद केजरीवाल कई विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं। वह दिल्ली में अध्यादेश के लेकर समर्थन चाहते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए वह जम्मू कश्मीर भी पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल तो समर्थन मांगने गये थे लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उन्हें ही आड़े हाथ ले लिया। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा धारा 370 को निरस्त करने पर दिल्ली के सीएम के रुख पर सवाल उठाए गये। उन्होंने सड़क पर आकर मीडिया से बात की। अरविंद केजरीवाल कई विपक्षियों से मिल रहे हैं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की आप की कोशिशों के बीच उमर अब्दुल्ला केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा।

उमर ने सुनाई केजरीवाल को खरी खरी

उमर अब्दुल्ला ने कहा, अरविंद केजरीवाल तब कहां थे जब अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था? लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। उन्होंने उस समय सरकार का समर्थन किया था और आज वह अन्य दलों से समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ केवल कुछ ही पार्टियों ने आवाज उठाई थी। केवल ममता बनर्जी की पार्टी और डीएमके ने उनका समर्थन किया था। केजरीवाल नहीं आये थे हमारा साथ देने के लिए।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए गैर-बीजेपी दलों के नेताओं के पास पहुंच रहे हैं ताकि संसद में लाए जाने वाले विधेयक के जरिए इसे बदलने की केंद्र की कोशिश विफल हो जाए। गौतमलब है कि अभी तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) महासचिव सोताराम येचुरी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के चंद्रशेखर राव, शिव सेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे, राष्वादी कांग्रेस पार्टी (राकापा) नेता शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रिमो ममता बनर्जी ने आप को इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है।



अध्यादेश विवाद क्या है?

केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में गुप-ए के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया था, जिसे आप सरकार ने सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रिम कोर्ट के फैसले के साथ धोखा बताया था। सुप्रिम कोर्ट द्वारा पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंपे जाने के एक सप्ताह बाद यह अध्यादेश आया। यह DANICS केडर के गुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करना चाहता है। शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यकारी नियंत्रण में थे।

कश्मीर एक हिमालयी क्षेत्र है जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों कहते हैं कि यह पूरी तरह से उनका है। यह क्षेत्र कभी जम्मू और कश्मीर नामक रियासत था, लेकिन ब्रिटिश शासन के अंत में उपमहाद्वीप के विभाजन के तुरंत बाद 1947 में यह भारत में शामिल हो गया। भारतीय शासन के खिलाफ एक अलगवादी विद्रोह के कारण 30 वर्षों से भारतीय प्रशासित पक्ष - जम्मू और कश्मीर राज्य में हिंसा हुई है।

भाजपा के सभी मुख्यमंत्रियों और उप-मुख्यमंत्रियों की बैठक आज

नई दिल्ली। अगले साल की शुरुआत में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके पहले इस साल के अंत तक पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है। कुल मिलाकर अगले एक साल तक देश में चुनाव ही चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी पारा हाई होना स्वाभाविक है। एक तरफ विपक्षी दलों ने 23 जून को पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के कई बड़े विपक्षी दल शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और

मल्लिकार्जुन खरगो भी बैठक में जाएंगे। वहीं, दूसरी ओर भाजपा ने भी 11 और 12 जून को भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप-मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के महासचिव बीएल संतोष और राज्य संगठनों के सचिव भी शामिल होंगे।

पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता का कहना है कि सभी मुख्यमंत्रियों और उप-मुख्यमंत्रियों की बैठक में पूरी तैयारी के साथ आने के लिए कहा गया है। पार्टी और

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले हो जाएं सतर्क

नई दिल्ली। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए चुकाए जाने वाले प्रीमियम और मैच्योरिटी की राशि पर टैक्स के नियमों को लेकर लोगों के बीच काफी गलतफहमी है। बजट 2023 में नियमों में किए गए बदलाव के बाद तो यह गलतफहमी और बढ़ी है। बजट 2023 में प्रस्तावित प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से लागू भी हो गए हैं। फिलहाल असेसमेंट इंयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने का काम भी तेजी से चल रहा है। फाइनेंस बिल 2023 में इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961, के सेक्शन 10 (10डी) में छूटे और सातवें प्रावधान जोड़े गए। 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी सेक्शन 10(10डी) के छूटे प्रावधान के मुताबिक यदि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए चुकाए गए प्रीमियम की राशि पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी एक वित्त वर्ष में 5 लाख रुपये से ज्यादा हुई तो बीमाधारक को उस पॉलिसी के लिए मिलने वाली मैच्योरिटी की राशि कर योग्य होगी।

ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक 1 अरब डॉलर का आईपीओ लाने के लिए कमर कस रही है। कंपनी अगले सप्ताह सिंगापुर और अमेरिका में निवेशकों के साथ अपनी निर्यात स्टॉक मार्केट लिस्टिंग पर बातचीत करेगी। आईपीओ के लिए यह कंपनी की निवेशकों के साथ पहली बातचीत होगी। मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने यह जानकारी दी। इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता ओला इलेक्ट्रिक की योजना वर्ष 2023 के अंत तक आईपीओ की मदद से 60 करोड़ डॉलर से 1 अरब डॉलर के बीच पूंजी जुटाने की है। बता दें कि ओला को सांचू बैंक और टेमासेक जैसे निवेशकों का समर्थन प्राप्त है। आईपीओ की पेशकश के लिए अभी काफी समय है, ऐसे में ओला भारत के ईवी बाजार की व्यावसायिक क्षमता को समझाने के लिए समय से पहले ही निवेशकों के साथ बैठकें कर रही है।

7.2% की रियल जीडीपी देश और अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्धि

नई दिल्ली। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने वर्ष 2023 में 7.2 प्रतिशत का वास्तविक जीडीपी दर हासिल करने को बड़ी देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए एक त्वरित उपलब्धि है। साथ ही मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह भी कहा कि 7.2% का रियल जीडीपी ग्रोथ हासिल करने में आम लोगों का भी अहम योगदान है। उनके समेत प्रयासों से ही हम यह विकास दर हासिल कर पाए हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि 2026 में जब रियल जीडीपी के वास्तविक आंकड़े आएं वे वर्तमान के संभावित आंकड़ों से और मजबूत हो सकते हैं। वित्त वर्ष 2023 के रियल जीडीपी के वास्तविक आंकड़े 7.2% से भी अधिक हो सकते हैं।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, जीई के बीच प्रस्तावित इंजन सौदे से रक्षा उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली। जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच भारत में जेट इंजनों के विनिर्माण के लिए प्रस्तावित सौदे से अमेरिकी और भारत के रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि दोनों कंपनियां 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अतिथि में आईआरए के आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान इस सौदे की घोषणा करेंगी। दोनों पक्ष इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। उद्योग के विशेषज्ञों को उम्मीद है कि लंबे समय से प्रतीक्षित सौदे का दोनों देशों के बीच संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका भारत कारोबारी परिषद के अध्यक्ष अतुल केशव ने बताया, 'दोनों सरकारें इस सौदे को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूँ।

स्टोल प्रमुख समाचार

टेस्ट क्रिकेट में रवींद्र जडेजा ने रवा इतिहास

लंदन। भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने हमवतन बिशन सिंह बेदी को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में देश के सबसे सफल बाएं हाथ के स्पिनर बन गए। जडेजा ने द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में, जडेजा ने पहली पारी के दो शतकों, स्टीव स्मिथ (34) और ट्रैविंस हेड (18) को पारी का अंत किया। जडेजा ने नौ ओवर में 2/25 के आंकड़े के साथ दिन का अंत किया।

अब 65 टेस्ट मैचों में जडेजा ने 24.25 की औसत और 2.44 की इकॉनमी रेट से 267 विकेट लिए हैं। बिशन सिंह बेदी के 67 मैचों में 266 विकेट हैं। कुल मिलाकर, जडेजा टेस्ट में चौथे सबसे सफल बाएं हाथ के स्पिनर हैं। वह श्रीलंका के रंगना हेराथ (93 मैचों में 433), डेनियल विलोरी (113 मैचों में 362) और इंग्लैंड के डेरेक अंडरवुड (86 मैचों में 297 विकेट) से पीछे हैं।

2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, जडेजा ने आठ मैचों में नौ पारियों में 32.75 की औसत से एक अर्धशतक के साथ 262 रन बनाए हैं। उन्होंने आठ मैचों में 21.33 की औसत और 2.78 की इकॉनमी रेट से 27 विकेट भी लिए हैं। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन के खेल समाप्त होने तक भारत से 296 रनों से आगे थी। खबर लिखे जाने तक चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया 329 रनों की बढ़त बनाए हुए है। उस्मान ख्वाजा (13) और डेविड वार्नर (1) को सिराज और उमेश यादव ने जल्दी भेजा जबकि रवींद्र जडेजा (2/25) ने पिछली पारी के शतकों स्टीव स्मिथ (34) और ट्रैविंस हेड (18) को आउट किया। भारत अपनी पहली पारी में 296 रन पर ढेर हो गया था।

आर्थिक/वणिज्य/वित्त

प्रमुख समाचार

गतांक से आगे... प्रह्लाद सबनानी

अभी हाल ही में किए गए एक आंकलन के अनुसार अमेरिका के 160 बड़े बैंकों (जिनके पास 500 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि की आस्तियां हैं) को 20,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। अमेरिका की रेटिंग संस्थाओं स्टैंडर्ड एंड पूअर्स एवं फिच ने कुछ बैंकों की रेटिंग घटाकर जंक श्रेणी में डाल दी है क्योंकि यह बैंक अपने जमाकर्ताओं को राशि वापिस करने की स्थिति में नहीं हैं। अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों को भी भारी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इनके अमेरिकी बांड्स में किए गए निवेश का बाजार कीमत कम हो गई है। सिटी बैंक समूह को 4,700 करोड़ अमेरिकी डॉलर, बैंक ऑफ अमेरिका को 2,120 करोड़

अमेरिकी डॉलर, जेपी मोर्गन चेज को 1,730 करोड़ अमेरिकी डॉलर, टरइस्ट फायनेन्शल को 1,360 करोड़ अमेरिकी डॉलर, वेल्ज फार्मा को 1,340 करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं यूएस बैंक कॉर्पो को 1,140 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। यह सभी बड़े बैंक हैं अतः इस नुकसान को सहन कर जाएंगे परंतु छोटे बैंक तो असफल (फैल) हो जाते वाले हैं। अभी तक दो बैंक (सिलिकॉन वैली बैंक एवं फिनेन्स्यर बैंक) बंद हो चुके हैं और 6 अन्य छोटे आकार के बैंकों (फ्रस्ट रिपब्लिक बैंक, वेस्टर्न अलाइन्स बैंक, पैकवेस्ट, यूएमबी फायनेन्शल सहित) पर गम्भीर संकट आ गया था। इन बैंकों में रोकड़ एवं तरलता का गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है एवं इनके पास अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है। इन बैंकों के शेयरों की कीमत पूंजी बाजार में 14 से



30 प्रतिशत के बीच गिर चुकी है। परंतु भारत में चूँक भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार भारतीय बैंकों को 4.5 प्रतिशत रोकड़ रिजर्व अनुपात एवं 18 प्रतिशत संवैधानिक रिजर्व अनुपात बनाए रखना होता है। जिसके अंतर्गत बैंकों को रोकड़ एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास उक्त राशि जमा रखना होती है, ताकि बैंकों को तरलता सम्बंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही, भारतीय बैंकों में प्रति जमाकर्ता के खाते में रुपए 5 लाख तक की जमा राशि का बीमा भी रहता है। अतः अमेरिकी बैंकों पर आए संकट का

प्रभाव भारतीय बैंकों पर पड़ता हुए दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि भारतीय बैंकों की उक्त वर्णित मजबूत स्थिति के चलते भारतीय रिजर्व बैंक की आज पूरी दुनिया में बहुत प्रशंसा हो रही है कि क्योंकि उसने भारतीय बैंकों को आर इतनी बर्बाद स्थिति में पहुंचा दिया है। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. शक्तिचोक दास को गवर्नर ऑफ द इयर अवार्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023 के लिए सेंट्रल बैंकिंग, एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान जर्नल की ओर से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। फिर भी कुल मिलाकर भारतीय बैंकों की आर्थिक स्थिति को लेकर अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न बैंकों के लिए जा रहे अपने निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे को लेकर कुछ बैंकों में स्थिति ठीक नहीं है। अतः कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पर इन बैंकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। बैंकों को अपने जमाकर्ताओं का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि उनकी जमा राशियां बैंकों में सुरक्षित रहें। अतिमहत्वाकांक्षी तरीके से त्रुणा वितरण करने के तरीकों से बचना भी जरूरी है। इससे बैंकों के व्यवसाय में तेज गति से वृद्धि तो जाती है परंतु इस प्रकार प्रदान किए गए त्रुणों की वसूली में कई बार कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कई बैंकों ने निष्पादन सम्बंधी नतीजे घोषित किए हैं, इन नतीजों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित कई बैंकों ने अपने व्यवसाय एवं लाभप्रदता में अतुलनीय वृद्धि दर्ज की है। इस वित्तीय निष्पादन को जारी रखने के लिए बैंकों को उक्त वर्णित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

चीन की चुनौती को भारत का जोजिला जवाब

मे. सरस चंद्र त्रिपाठी (रिटा.)

जिस गति से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार मूलभूत ढांचे का निर्माण कर रही है वह अभूतपूर्व और अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय इसलिए कि कोई विकसित और उन्नत तकनीकी दक्ष देश भी ऐसे दुरूह प्रोजेक्ट को प्रारम्भ करने से पहले सौ बार सोचेगा। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जोजिला सुरंग। समुद्र तल से 11,600 फुट ऊपर यह दर्रा दुरूहतामय दर्रा में एक है। जोजिला दर्रा (पास) इतना दुरूह है कि कम से कम 5-6 महीने हिमपात और हिम जमाव के कारण इस पर आवागमन सम्भव ही नहीं होता। यह पास कश्मीर क्षेत्र को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ता है। यह श्रीनगर से लगभग 100 किमी दूर करगिल जिले में स्थित है। लद्दाख को जोड़ने वाले मात्र दो ही पास (दर्रे) हैं, एक हिमाचल से होकर जाने वाला रोहतांग पास और दूसरा कश्मीर से जाने वाला जोजिला पास। ये दोनों ही पास लद्दाख को भारत की मुख्य भूमि से पूरे वर्ष जोड़ कर रखने में सक्षम नहीं हैं।

अक्टूबर से अप्रैल तक सम्पूर्ण लद्दाख क्षेत्र शांख नेतृत्व की सड़क मार्ग से कटा रहता है। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे टकराव और मूलभूत ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है और कर रही है। इन दोनों दर्रा के नीचे पहाड़ को चीरकर पूरे वर्ष प्रयोग किए जाने वाला राजमार्ग (आल वेदर रोड) बनाया जा रहा है। रोहतांग के विकल्प के रूप में अटल सुरंग तैयार हो चुकी है। अब जोजिला सुरंग की बारी है। इस सुरंग के निर्माण का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में किया। यह सुरंग लगभग 14 किमी लम्बी है। यह दो-तरफा सुरंग मार्ग जो एशिया में अपने तरह का सबसे लम्बा है। इस प्रोजेक्ट के महत्व को समझने के लिए इतना जान लेना ही काफी होगा कि इसे केन्द्रीय स्तर पर निरंतर निगमानी में बनाया जा रहा है। अप्रैल के महीने में जहां सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ जोजिला का दौरा करके निर्माण कार्य का जायजा लिया था वहीं दो दिन पहले लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने इस जगह का दौरा करके निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस सुरंग का निर्माण कार्य सरकार के शांख नेतृत्व की पहल पर हो रहा है। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के उपराज्यपाल तथा केन्द्रीय राजमार्ग मंत्री स्वयं इसका समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं। जम्मू-कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपये की लागत से 19 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत जोजिला में 6800 करोड़ रुपये की लागत से 13.14 किलोमीटर लंबी टनल व अप्रॉच रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह 7.57 मीटर ऊंची घोड़े की नाल के आकार की सिंगल-ट्यूब, 2-लेन सुरंग है, जो कश्मीर में गांदरबल और लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास शहर के बीच हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे से गुजरेगी। परियोजना में एक स्मार्ट टनल प्रणाली शामिल है, जिसका निर्माण न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके किया गया है। यह सीसीटीवी, रेडियो कंट्रोल, निर्बाध बिजली आपूर्ति, वेंटिलेशन जैसी सुविधाओं से लैस है। इस परियोजना में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से भारत सरकार के 5000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट के अंतर्गत 13,153 मीटर की मुख्य जोजिला टनल, कुल लंबाई 810 मीटर की 4 पुलिया, 4 नीलग्रार टनल, कुल लंबाई 4,821 मीटर, 8 कट एंड कवर कुल लंबाई 2,350 मीटर और तीन 500 मीटर, 391 मीटर और 220 मीटर ऊर्ध्वाधर वेंटिलेशन शाफ्ट प्रस्तावित हैं। अभी तक जोजिला टनल का 28 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इस टनल के बनने से लद्दाख के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी हो जाएगी। वर्तमान में जोजिला दर्रे को पार करने में औसत यात्रा समय कभी-कभी तीन घंटे लगते हैं, इस सुरंग के पूरा होने के बाद यात्रा का समय घटकर 20 मिनट रह जाएगा। यात्रा के समय में कमी से अंततः ईंधन की बचत के अलावा कई फायदे होंगे।

ललित गर्ग

कुछ शक्तिवादी देशों के आजादी के अमृतकाल को अमृतमय बनाने में जुटी हैं, वहीं कुछ संकीर्ण, साम्प्रदायिक, उन्मादी एवं अलगाववादी शक्तियां देश को तोड़ने एवं धुंधलाने में लगी हैं। वोटबैंक के नाम पर लोगों को अलग-अलग खेमों में बांटने, तुष्टिकरण एवं उन्मादी काली शक्तियों को प्रोत्साहन देने एवं ज्वाला बनाने का काम देश के लिये घातक एवं नुकसानदेह है। वोटबैंक की राजनीति सभी देशों में होती है, पर ऐसा करते हुए भी मर्यादा एवं देश की एकता का ध्यान भी रखा जाता है। कानून का राज कायम रखने और विश्व शांति के खतरों को कमतर करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। जिन देशों में इसका ध्यान नहीं रखा जाता, वहां जल्दी ही लोकतंत्र भीदुर्गत में बदल जाता है, दूट एवं बिखर कर रसातल में चला जाता है। धार्मिक कट्टरपंथियों एवं उन्माद के आगे नतमस्तक रहे पाकिस्तान को देखकर इस समस्या की गंभीरता को समझा जा सकता है। कनाडा में पिछले कुछ समय से और खासकर जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में, वहां बसे सिखों को साधने के लिए जिस तरह खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वह भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता की बड़ी वजह है, लेकिन यह कनाडा के लोकतंत्र के लिये भी बड़ा खतरा बनने का संकेत है।

कनाडा में बेलगाम होते खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियां किसी से छिपी नहीं, लेकिन अब उनका दुस्साहस इतना अधिक बढ़ गया है कि वे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का खुलेआम जश भी मनाए लगे हैं। कनाडा के प्रेसटन नगर में खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरह एक परेड निकाली और उसमें इंदिरा गांधी की हत्या करते हुए दिखाया गया, इसमें दो सिखों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को गोली मारते दिखाया गया। वेह बेहद त्रासद, शर्मनाक और घिनौना है। यह परेड करीब पांच किमी तक निकाली गई। स्पष्ट है कि कनाडा की पुलिस आतंक का महिमांडन करने वाली इस घिनौनी परेड को चुपचाप देखती रही। आतंकवाद का ऐसा खुला, लज्जाजनक और नग्न समर्थन कनाडा के साथ सभ्य समाज को शर्मसार करने वाला है। निश्चित ही इससे दुनिया में पनप रहे आतंकवाद को बल मिलेगा। यह आज सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है।

भारत में भी कनाडा की ही भांति वोट बैंक ही पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद एवं जम्मू-

बेलगाम होते खालिस्तान समर्थक



कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद पनपने का बड़ा कारण बना था। इस घटना के सामने आने के बाद भारत सरकार की तीखी प्रतिक्रिया जाबज है। ऐसी घटनाओं के कारण दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस नेताओं ने भी घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें बाँकर किसी राजनीति के पक्ष व विपक्ष दोनों के सुर का एक होना जरूरी है। ऐसा ही दिखा भी, दिखना भी चाहिए। पंजाब में खालिस्तानी स्वर उग्र हो रहे हैं, इसको उग्रता देने में कनाडा आदि देशों में रह रहे खालिस्तान समर्थक सिखों से मिल रही आर्थिक मदद एवं अन्य प्रोत्साहन बड़े कारण हैं। अब एक बार फिर खालिस्तान समर्थक तत्व देश के अंदर और बाहर सक्रिय हो रहे हैं। कनाडा उनके लिए एक बड़ा केंद्र एवं आश्रय-स्थल बनकर उभरा है। और यह वहां अपनी तरह का कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी वहां से एक अलग देश खालिस्तान बनाए जाने के सवाल पर जनमत संग्रह करवाए जाने की खबर आई थी। खालिस्तान समर्थक कभी भारतीय उच्चायोग को घेरते हैं, कभी भारतीयों पर हमले करते हैं और कभी मंदिरों को निशाना बनाते हैं।

कनाडा सरकार हर बार इन खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहकर चुप्पी साध लेती है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे ताजा वीडियो को हालांकि सबसे पहले कांग्रेस नेताओं ने मुद्दा बनाया, लेकिन फिर सरकार भी इस पर जागरूक हुई है। ऐसी घटनाएं न तो भारत-कनाडा रिश्ते के लिए

अच्छी हैं और न कनाडा के लिए। बहरहाल, इससे यह साफ हो जाता है कि कनाडा में हिंसा की वकालत करने वाले अतिवादी और अलगाववादी तत्वों पर कोई अंकुश नहीं रह गया है। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके ने हालांकि इस घटना की निंदा की और कहा कि उनके देश में नफरत, द्वेष और हिंसा के महिमांडन के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन ऐसे औपचारिक बयान जारी कर देना काफी नहीं है। उनका बयान लीपापोती के अलावा और कुछ नहीं, बयोंकि सच यही है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की कट्टरता और नफरत को पालने-पोसने का काम बड़ी ही बेधर्मी से किया जा रहा है, वहां की सरकार खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। इसी के चलते उनका दुस्साहस बढ़ता चला जा रहा है। वैसे तो उग्रपंथी खालिस्तान समर्थक दुनिया के कई देशों में सक्रिय हैं, लेकिन वे जितने कनाडा में बेलगाम हैं, उतने अन्यत्र नहीं। कनाडा को समझना होगा कि आतंकवाद, अलगाववाद, नफरत और हिंसा की आग सबसे पहले उन देशों को जलाती है जो इसे हवा देते हैं। ऐसे देशों की दुर्गति के उदाहरण सबके सामने हैं। उन देशों के अनुभव से समय रहते सबक लेना चाहिए।

कनाडा में खालिस्तान समर्थन का बड़ा कारण यह है कि कनाडा की वर्तमान सरकार उस राजनीतिक दल के समर्थन के भरोसे सत्ता में है, जिसमें खालिस्तान समर्थक भरे पड़े हैं। कनाडा की सरकार संकीर्ण राजनीतिक कारणों से खालिस्तान समर्थकों की भारत-विरोधी

अराजक, घृणित और नफरत फैलाने वाली हरकतों की जानबूझकर अनदेखी कर रही है। यह अच्छा हुआ कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बिना किसी लाग लपेट कहा कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा है और वहां खालिस्तान समर्थकों को मिल रहे समर्थन से दोनों देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। चूंकि इसके आसार कम हैं कि भारत सरकार की आपत्ति के बाद कनाडा सरकार खालिस्तान समर्थक अराजक तत्वों को समर्थन देने से बाज आएगी, इसलिए यह आवश्यक है कि उस पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया जाए।

भारत के लिये जरूरी है कि यहां सभी राजनीतिक दल इन अति-संवेदनशील एवं देश तोड़क मुद्दों पर एकमत हों। राजनीति के पोषण के बिना खालिस्तानी आतंक उग्र नहीं हो सकता, उनको भड़का कर राजनीति करने वाले दलों से सवधान होने की जरूरत है। खालिस्तान समर्थक अपनी आतंकवादी गतिविधियों एवं हरकतों से देश की एकता एवं अखण्डता को खंडित करना चाहते हैं, ये तत्व अपनी इस तरह की हरकतों के जरिए उस आतंकवाद की ओर से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे कदम उठाने पड़े और जिसके चंगुल में पंजाब आगे भी कई साल तक फंसा रहा, त्रासदी झेलता रहा, डरा एवं सहमा रहा, न जाने कितने परिवार इस चक्र में हबाद हो गए, कितने लोगों को जान देनी पड़ी। अनगिनत कुर्बानियों के बाद पंजाब जैसे-तैसे उस मुश्किल दौर से निकला और पहले की तरह अखण्ड पंजाब से विकास की नई कहानियां लिखने लगा। लेकिन अब पुनः पंजाब को उसी खूनी मंजर एवं खौफनाक दौर की ओर अग्रसर करना आजादी के अमृतकाल को धुंधला देगा। जरूरत है तुष्टिकरण हटे, संकीर्ण दायरों से बाहर आये एवं उन्माद भी हटे। अगर भारत माता के शरीर पर इतना बड़ा घाव करके हम कुछ नहीं सीख पाये, आस्था को उन्माद बनाने से नहीं रोका, वोट के लिये धर्म की राजनीति करना नहीं छोड़ा और संवर्धन सम्भाव की सबका को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया तो यह हम सबका का दुर्भाग्य होगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

गरुडोपनिषद् (भाग-6)

गतांक से आगे...
तुम चाहे गुलिक के दूत हो अथवा स्वयं गुलिक हो। उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्द्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को (ब्रह्मविद्या) जो कि विषों की विष है। विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है। उसने इन्द्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इन्द्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है, स्वाहा। तुम चाहे पौण्ड्रिकाति के दूत हो अथवा स्वयं कालिक हो उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्द्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को (ब्रह्मविद्या) जो कि जियों की विष है। विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है, उसने इन्द्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इन्द्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है, स्वाहा। तुम चाहे नागक के दूत हो अथवा स्वयं नागक हो।

उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्द्धित हो रहा है। ऐसे उस विष को (ब्रह्मविद्या) जो कि विषों की विष है। विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है। ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है, उसने इन्द्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर नष्ट कर दिया है। इस विष को विनष्ट करने में इन्द्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है, स्वाहा। तुम चाहे मकड़ी, बड़ी (श्रेष्ठ) मकड़ी हो चाहे वृश्चिक (बिच्छू) हो, चाहे घुड़दंडी सर्प हो और चाहे स्थावर जंगम हो। उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्द्धित एवं संचरित हो रहा है। ऐसे उस विष को (ब्रह्मविद्या) जो कि विषों की विष है। विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है। ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है, उसने इन्द्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर नष्ट कर दिया। इस विष को विनष्ट करने में इन्द्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है, स्वाहा।

क्रमशः ...



बाल श्रम रोकने के लिए मनाया जाता है 'अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस'

अमृता गोस्वामी

बाल श्रम की वैश्विक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने तथा बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने हेतु आवश्यक प्रयासों के क्रियावित किए जाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 12 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस' मनाया जाता है। यह दिन बच्चों को एक अच्छा भविष्य निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (आईएलओ) द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी।

आईएलओ और यूनिसेफ की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्वभर में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़कर 16 करोड़ हो गई है, इस रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई है कि कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप 2022 के अंत तक वैश्विक स्तर पर 90 लाख और बच्चों को बाल श्रम में धकेल दिए जाने का खतरा है। आज बाल श्रम निषेध दिवस पर हमारा यह जानना जरूरी है कि बाल श्रमिक किन्हें कहा जाता है और बाल श्रमिकों पर बाल श्रम के क्या कुप्रभाव होते हैं।

कानून के अनुसार बाल श्रमिक वह बच्चे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, राष्ट्रीय कानून द्वारा



परिभाषित न्यूनतम कानूनी उम्र से पहले किसी व्यावसायिक कार्य में लगाया जाता है इसके अलावा गुलामी या गुलामी के समान प्रथा अथवा किसी अवैध गतिविधियों में बच्चों का शामिल होना भी बाल श्रम के अंतर्गत आता है, वहीं ऐसे कार्य जो बच्चों या किशोरों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत विकास को प्रभावित नहीं करते हैं या जिन कार्यों का उनकी स्कूली शिक्षा पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता हो बाल श्रम नहीं कहलाते। शिक्षा के समय के अलावा या छुट्टियों के दौरान किसी पारिवारिक नैतिक व्यवसाय में बच्चे का साथ देना उसकी हॉबी या एक सामाजिक सोच को प्रेरित करता है, अतः यह भी बाल श्रम नहीं है। बाल श्रमिक में वे बच्चे चाहे लड़के हों या लड़कियां भी शामिल हैं जो आपदाग्रस्त, दिव्यांग, एचआईवी पीडित, अनाथ, अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, विस्थापित, हिंसा एवं युद्धग्रस्त इलाकों से हैं और बाल श्रम करते हैं।

बाल श्रम एक सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समस्या है जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। बाल श्रम का असर बच्चों पर इस तरह पड़ता है कि वे शिक्षा से दूर होते जाते हैं, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार की संभावना रहती है, उन्हें भिक्षावृत्ति की ओर प्रवृत्त किया जा सकता है, उनका शारीरिक शोषण किया जा सकता है साथ ही उन्हें असुरक्षित प्रवास और विस्थापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाल श्रम से जुड़े बच्चे अपने बचपन की मौलिकता, खेलकूद और मनोरंजन से वंचित रह जाते हैं।

ज्ञात हो कि 20 नवंबर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' को अपनाया गया था, जिसमें 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को किसी भी प्रकार के व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एनसीआरसी को भारत द्वारा वर्ष 1992 में अनुमोदित किया गया था। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है। जबकि 14 से 18 वर्ष से किशोरों पर केवल खतरनाक व्यवसायों में कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

रूस का बढ़ता सैन्य खर्च और खोती हुई साख

नीरज कुमार दुबे

यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के बढ़ते कदम अब रुक-से गए हैं क्योंकि जानमाल की भारी हानि रूस को भी हुई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करें। दरअसल, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से ही रूस पश्चिमी देशों की ओर से लगाये गये तमाम प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध और बढ़ गये जिससे रूस की अर्थव्यवस्था भारी दबाव में आ गयी। इसके साथ ही पुतिन की सोच के विपरीत युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है जिससे रूस का नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। देखा जाये तो शुरु में रूस ने एक छोटा सैन्य अभियान समझ कर जो युद्ध शुरू किया था वह अब अंतहीन होता दिख रहा है। रूस के लिए यह संघर्ष एक लंबा और महंगा युद्ध बन गया है।

द इकोनॉमिस्ट ने अनुमान लगाया है कि रूस का सैन्य खर्च एक वर्ष में पांच खरब रुबल (49 अरब पाउंड) या उसके सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत है। हालांकि जर्मन कार्टेसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (जीडीएपी) का अनुमान है कि युद्ध में रूस का सैन्य खर्च यूएसडी 90 अरब (72 अरब पाउंड), या जीडीपी के पांच प्रतिशत से अधिक है। युद्ध में जिस तरह बेहिसाब खर्च हो रहा है उससे अब रूसियों का हौसला भी जवाब देने लगा है। जहां तक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की बात है तो उसने रूस की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रतिबंधों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों, विदेशी मुद्रा और उत्पादों तक रूस की पहुंच को क्षमता को प्रभावित किया है। साथ ही जिस दर से रूसी सेना को इस समय रक्षा उपकरण और गोला-बारूद मित्र देशों से मिल रहा है, वह भी देश के रक्षा उद्योग पर दबाव



डाल रहा है। इस स्थिति से उबरने के लिए रूस के सामने विकल्प यह है कि वह एक बार में निर्णायक सफलता हासिल करने के लिए अपने सैन्य प्रयासों को बढ़े पैमाने पर बढ़ाये। अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो यूक्रेन को दुनिया से मदद मिलती रहेगी क्योंकि यह युद्ध भले दो देश लड़ रहे हों मगर इससे वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में रूस को रोकने और यूक्रेन को जिताने के लिए दुनिया के बड़े देश यूक्रेन को समर्थन देते रहेंगे। अब तक के युद्ध को देखें तो रूस ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद खो दिया है। मार्च 2023 में ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के मंत्री जेम्स हेप्टे ने अनुमान लगाया था कि रूस ने 1,900 म्यूथ्य युद्धक टैंक, 3,300 अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 73 चालक दल वाले फिक्सड विंग विमान, सभी प्रकार के कई सौ बिना चालक दल वाले हवाई वाहन (यूपीवी), 78 हेलीकॉप्टर, 550 ट्यूब आर्टिलरि सिस्टम, 190 रॉकेट आर्टिलरि सिस्टम और आठ

नौसैनिक जहाज खो दिए हैं। इसके अलावा, रूस को कई महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है। दरअसल सटीक निशाना लगाने वाले कई हथियारों के लिए रूस भी विदेशी तकनीक पर निर्भर है जोकि प्रतिबंधों के चलते अब उसे मिल नहीं रही है। इस तरह की भी रिपोर्टें हैं कि रूसी सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकशः उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अमेरिकी कंपनियों द्वारा ही निर्मित होते हैं। शायद यही कारण है कि इस समय रूसी सेना निम्न श्रेणी के हथियारों का ज्यादा उपयोग कर रही है और अत्याधुनिक तकनीक वाले हथियारों का उपयोग संयम के साथ किया जा रहा है। रूस ऐसा इसलिए कर रहा है कि स्थिति ज्यादा बिगड़ती है तब इनसे असल काम लिया जा सके। ऐसा भी सामने आया है कि जिन तोपों के गोलों पर रूस को बहुत भरोसा था वह भी अब कम पड़ रहे हैं।

रूस पर वैश्विक प्रतिबंधों का कितना असर पड़ रहा है यह समझना ही तो आप यूएस थिंकरटैंक सेंटर फॉर सिक्वोरिटी एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट को देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुमानों के हवाले से बताया गया है कि रूस इतना परेशान हो चुका है कि वह अपने जिन 6000 से अधिक सैन्य उपकरणों को बदलना या

अपग्रेड करना चाहता था, उस काम को उसने रोक दिया है क्योंकि उसे विदेशी तकनीक और रक्षा उत्पादन से जुड़े सारो-सामान नहीं मिल पा रहे हैं। रूसी टैंकों और सैन्य विमानों का अपग्रेड भी इन प्रतिबंधों की वजह से रुक गया है।

रूस से जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं वह दर्शा रही हैं कि अब पुतिन की सरकार घरेलू स्तर पर ही हथियारों को पूर्ण रूप से निर्मित करने पर जोर दे रही है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दमित्री मेदवदेव ने हाल ही में 1,500 आधुनिक टैंकों के उत्पादन की योजना पेश की है। रूसी संवाद समिति तास ने बताया है कि मेदवदेव निगरानी ड्रोन के बड़े पैमाने पर उत्पादन की भी योजना बना रहे हैं। बताया जाता है कि सरकार हथियार निर्माताओं को पर्याप्त ऋण प्रदान कर रही है और यहां तक कि ऐसा करने के लिए बैंकों को आदेश भी जारी किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि कई रूसी हथियार संयंत्र ससाह में छह या सात दिन तक तीन शिफ्टों में काम कर रहे हैं और कर्मचारियों को अधिक वेतन की पेशकश भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वे उन जैसी हथियार प्रणालियों का उत्पादन बड़ा सकें जिनका रूस प्रतिबंधों के चलते आयात नहीं कर पा रहा है।

बहरहाल, रूस का बढ़ता सैन्य खर्च और खोती हुई साख दुनिया को भारत के उस संदेश का महत्व एक बार फिर बताती है जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। युद्ध से भले रूस ने यूक्रेन के कुछ इलाके जित लिये हों लेकिन अपनी सैन्य ताकत का उसने जीता घमंड था वह चूर-चूर हो चुका है। एक छोटे-से देश को सीमित संसाधनों वाली सेना ने जिस तरह विश्व की एक महाशक्ति को डेढ़ साल से उलझा रखा है वह वैश्विक इतिहास की बड़ी घटनाओं में शुमार हो चुका है।

बापू की दिनचर्या

दिन का भोजन



बापू दिन का भोजन सामान्यतः ग्यारह बजे किया करते। सन् 1913 में फिनिस-आश्रम में दिन में ग्यारह बजे वे भोजन की मेज पर बैठ जाते। टॉलस्टॉय फार्म में भी दिन के भोजन का यही समय था। सन् 1925 में साबरमती में भी वे ग्यारह बजे और सन् 27 में साढ़े दस बजे के लगभग भोजन करते। आगा खॉं महल में साढ़े दस बजे, नोवाखाली में ग्यारह बजे और सेवाग्राम में साढ़े दस-ग्यारह बजे वे भोजन करते। अंतिम दिन का आहार उन्होंने दिन में ग्यारह बजे किया। इसके पश्चात् उस दिन बापू ने आभा बहन गांधी से बंगला पाठ पढ़ा और स्वयं बंगला लेखन भी किया। उन दिनों उनके दिन के आहार का यही समय था। बापू सभी कार्यों की भाँति भोजन में भी समय की पाबंदी रखते। आश्रम में भोजन के लिए घंटी बजती। यदि कोई व्यक्ति देर से पहुँचता और भोजनालय का दरवाजा बंद हो जाता, तो उस समय वे छोटा-सा वक्तव्य दे डालते। वे भोजन को रेलगाड़ी समझने के लिए कहते। उनका कहना था कि छह बजे की गाड़ी पकड़ने के लिए कम-से-कम पंद्रह मिनट पहले स्टेशन पर उपस्थित होना आवश्यक है। छह बजकर पाँच मिनट पर स्टेशन पहुँचनेवाले को गाड़ी नहीं मिल सकती। उसे अगली गाड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह उपदेश दूसरों के लिए होता, ऐसा नहीं। वे अपने लिए इसी नियम को लागू करते देखते गए/बापू को एक बार संभवतः साबरमती आश्रम में कुछ कारणवश भोजनागार में पहुँचने में देर हो गई। उन दिनों वे तथा वहाँ के सभी लोग आश्रम के भोजनालय में भोजन करते। भोजन के समय दो घंटियाँ बजतीं। दूसरी घंटी तक जो न पहुँच पाता, उसे दूसरी पॉक के लिए बरामदे में इंतजार करना पड़ता। किवाड़ बंद कर दिए जाते, जिससे बाद में कोई आ न सके। हाँ, तो चेतावनी की अंतिम घंटी बज चुकी थी। द्वार बंद था। बापू बाहर खड़े थे। बैठने के लिए कोई बेंच या कुर्सी वहाँ नहीं थी। इस पर हरिभाऊजी उपाध्याय ने, जो स्वयं पिछड़ गए थे, बापू से कहा-कुर्सी लाओ? बापू ने इन्कार करते हुए उसी में सच्चा आनंद अनुभव किया और सजा भुगतने के लिए कहा। सन् 1928 का एक दूसरा प्रसंग है। बापू एक बार दोपहर के भोजन के समय रसोईघर में ठीक समय पर न पहुँच सके तो घंटी बजानेवाले भाई उनकी प्रतीक्षा करने लगे।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

जिला सीईओ ने ओड़गी क्षेत्र के विभिन्न निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

सूरजपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री लीना कोसम के द्वारा सूरजपुर जिले के ओड़गी विकास खण्ड के ग्राम पंचायत इन्दरपुर में अमृत सरोवर अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। कुदरगढ़ में रीपा योजना अन्तर्गत गोबर पेन्ट निर्माण इकाई, चुनरी निर्माण इकाई, टेन्ट एवं बर्तन इकाई में कार्यरत स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ चर्चा किया गया एवं उत्पादन बढ़ाने एवं मार्केटिंग बढ़ाने के संबंध में निर्देश दिया गया। तत्पश्चात गिरजापुर एवं ओड़गी में नरवा उपचार के अन्तर्गत गेबियन, अन्डरग्राउण्ड डाइक निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात् पालदंनौली में अमृत सरोवर योजना अन्तर्गत तालाब निर्माण का निरीक्षण किया गया, एवं बांक में प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहीयों से चर्चा किया गया। आवास को शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा गया, नरवा उपचार अन्तर्गत गेबियन, अन्डरग्राउण्ड डाइक निर्माण कार्य एवं आवर्ती चराई का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात् उन्होंने लांजित एवं चिकनी में अमृत सरोवर योजना अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रणबीर साय जनपद पंचायत ओड़गी, सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा श्री के.एम. पाठक, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, श्री मेहेन्द्र कुशवाहा संबंधित तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत के संपर्क, सचिव, रोजगार सहायक एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में करीब 5 लाख नए मतदाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार नए मतदाताओं की संख्या को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने नए पोलिंग बुध बनाकर वोटरों की भीड़ नियंत्रित करने की योजना बनाई है। जात हो कि छत्तीसगढ़ में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इस बार चुनाव में करीब 5 लाख नए मतदाता भी जुड़ गए हैं, इनके लिए मतदान केंद्रों की तलाश शुरू कर दी गई है। 5 लाख नए मतदाता यदि पुराने पोलिंग बुधों में मतदान के लिए पहुंचें तो भीड़ बढ़ जाएगी और इसे नियंत्रित करना काफी मुश्किल होगा। यही वजह है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 700 बुधों की तलाश की जा रही है। इनमें रायपुर, बिलासपुर दुर्ग जैसे बड़े शहरों को विहित किया गया है, जहां सर्वाधिक मतदाता बढ़ें हैं। आयोग की मंशा ये है कि ऐसे पुराने मतदान केंद्र जहां 4-5 बूथ हैं, उनको संख्या कम कर दी जाए और इसके स्थान पर नए बुध बनाए जाएं। रायपुर में आई केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने शुक्रवार को प्रदेश के 15 जिलों के कलेक्टर-एसपी तथा आला अपसरों के साथ मंथन किया। पुर्वार को 18 जिलों के अपसरों से डेटा लिया गया था।

मध्य रेलवे मजदूर संघ के जौनल महामंत्री ने किया डीजल लोको शेड का दौरा

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ बिलासपुर जौन के महामंत्री संतोष पटेल ने शुक्रवार को अपने जौनल सहयोगी सदस्यों के साथ डीजल लोको शेड रायपुर एवं मण्डल रेल विक्सालय डब्बू आर एस कालोनी का दौरा किया। इस दौरान डीजल लोको शेड रायपुर के अध्यक्ष राजेन्द्र धीवर व सचिव मिथुन मानिकपुरी ने अपने शाखा कार्यकर्ताओं के साथ महामंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। महामंत्री पटेल ने डीजल लोको शेड रायपुर के वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक अभियंता शुभम वर्मा से सौजन्य मुलाकात की तथा डीजल लोको शेड रायपुर के वर्तमान महत्वपूर्ण समस्याओं पर डीजल लोको शेड रायपुर के अधिकारी शुभम वर्मा से विस्तृत चर्चा की और इसे कर्मचारी हित में शीघ्र अतिशोध ही समाधान निकालने का आग्रह किया जिसे डीजल लोको शेड रायपुर के वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक अभियंता वर्मा जी ने जल्द ही इन समस्याओं का उचित समाधान निकालने का भरोसा दिलाया।

10वीं-12वीं के टॉपर बच्चों ने की हेलीकॉप्टर की सैर

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले बच्चों ने आज हेलीकॉप्टर राइड का मजा लिया। टॉपर्स बच्चों ने हेलीकॉप्टर्स से उतरने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल से धन्यवाद करते हुए आगे भी इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले बच्चों को हेलीकॉप्टर्स से सैर कराया जाता है। इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले बच्चों को आज पुलिस लाईन हेलीपैड से हेलीकॉप्टर में बिठाकर आसमान की सैर कराई गई। आज सुबह करीब 10 बजे से ही राजधानी के आसमान पर हेलीकॉप्टर्स की गडगडहट शुरू हो गई थी। बोर्ड परीक्षा में मेरिट में स्थान पाने वाले करीब 90 बच्चों को आज सीएम के निर्देशानुसार हेलीकॉप्टर में बिठाकर राजधानी की सैर कराई गई। पहली बार उड़नखटोले को इतने करीब से देखने और उस पर बैठकर हवाई सैर करने वाले बच्चों के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अधिकारी बच्चे अपने-अपने माता-पिता अथवा परिजनों के साथ पुलिस लाईन मैदान पहुंचे थे। बच्चों के साथ ही उनके माता-पिता और परिजन भी अपने लाडले-लाडली को हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान की सैर करता देख खुशी से गदगद हो गए थे।

हर समाज और वर्ग के लोगों का विकास हमारा ध्येय: बघेल

मुख्यमंत्री चंद्रनाथ कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक अधिवेशन में हुए शामिल, कुर्मी समाज के छात्रावास भवन का किया उद्घाटन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को कवर्धा के गांधी मैदान में चंद्रनाथ कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि कुर्मी समाज कृषि आधारित समाज है और प्रारंभ से ही खेती-किसानी से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के कृषक वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कृषकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज स्वर्गीय डॉ. खूबचंद बघेल, स्वर्गीय डॉ. चंद्रलाल चंद्राकर और अन्य पूर्वजों का सपना था कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो और छत्तीसगढ़िया किसान, मजदूर, श्रमिक, गरीब तथा पिछड़े तबकों की स्थिति में सुधार हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित सभी क्षेत्रों छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर हो। हमने साढ़े चार सालों में समाज के सभी वर्ग के लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इस मौके पर समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को किसानों के प्रतीक नागर, तलवार और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने समाज द्वारा निर्मित छात्रावास भवन का उद्घाटन भी किया। अधिवेशन में पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर, अपेक्षक बँक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, रायपुर पिछड़ा वर्ग



आयोग के सदस्य श्री महेश चंद्रवंशी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद हमने सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया। समर्थन मूल्य में धान की साथ-साथ कोदो, कुटकी, रागी, मक्का और गन्ना खरीदी कर रहे हैं। इससे किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। राजीव गांधी

किसान गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से किसानों, ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति बदलाव आया है। राज्य के किसान कर्ज से चिंता मुक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की किसानों हितैषी नीतियों के चलते राज्य में खेती-किसानी को लेकर लोगों में रूचि बढ़ी है। खेती छोड़ चुके लोग भी अब खेती-किसानी से जुड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या और धान उर्पाजन की मात्रा बढ़ते-साढ़े चार सालों में दोगुनी हो गई है। पंजीकृत धान का रकबा बढ़कर अब 32 लाख हेक्टेयर हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हम देश के सभी राज्यों के भ्रमण कर रहे हैं और किसानों से मिले हैं। अन्य राज्यों के किसान भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों के जैसा उन्हें भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाभ मिले। आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। छत्तीसगढ़ में हमारे ग्रामीण, किसान, पशुपालक गोबर बेचकर मोटर साइकिल खरीद रहे हैं। गोबर से वर्मी कम्पोस्ट,

प्राकृतिक पेंट तैयार किया जा रहा है, जिसका उपयोग सभी शासकीय कार्यालयों के रंग-रोगन में हो रहा है। गौठानों में स्थापित रीपा के माध्यम से महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिलने लगा है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि पुरखे के सपनों के अनुरूप आप सबके सहयोग से आज यहां छात्रावास बनकर तैयार हुआ है। आज वनांचल क्षेत्र सुकमा, बस्तर के विधायी मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ी परम्परा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरेली, तीजा, दशहरा और छत्तीसगढ़ी त्योहार में सार्वजनिक अवकास घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और खाना-पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सम्मान में राज गीत बनाया गया है, जिससे अब लाता है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार है और पुरखा के सपने साकार हो रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अध्यक्ष लाल बहादुर चंद्रवंशी, लालजी चंद्रवंशी, शिवकुमार चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य तुकाराम चंद्रवंशी, नीलकंठ चंद्रवंशी एवं समाजिक पदाधिकारी सहित समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

छग उच्चन्यायालय में 12 से नए रोस्टर सिस्टम के माध्यम से होगी सुनवाई



अपील, वर्ष 2022 के रिट अपील, डिवीजन बेंच में सुने जाने वाले सभी रिट मामलों की सुनवाई होगी।

15 सिंगल बेंच में प्रतिदिन होगी याचिकाओं की सुनवाई

इसके अलावा 15 सिंगल बेंच में प्रतिदिन याचिकाओं की सुनवाई होगी। पहला सिंगल बेंच चीफ जस्टिस का होगा। इसमें आर्बिट्रेशन एक्ट से संबंधित याचिका की सुनवाई करेंगे। स्पेशल बेंच संबंधित रिट अपील, कमर्शियल डिवीजन बेंच, डिवीजन बेंच में सुने जाने वाले सिविल के मामले, कंपनी अपील और वर्ष 2020-21 के क्रिमिनल अपील से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करेंगे। तीसरी डिवीजन बेंच जस्टिस संजय अरविंद चंदेल का होगा। इसमें डिवीजन बेंच में सुने जाने वाले सभी प्रकार के क्रिमिनल

बेंच में वर्ष 2018 से लंबित रिट याचिकाओं की सुनवाई होगी। जस्टिस संजय अग्रवाल के सिंगल बेंच में द्वितीय अपील, प्रथम अपील, ट्रांसपर याचिका सिविल की सुनवाई होगी।

हर शुक्रवार को विशेष बेंच की सुनवाई

इसके साथ ही जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के सिंगल बेंच में वर्ष 2012 से लंबित क्रिमिनल रिटिवजन से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी। हर शुक्रवार को विशेष बेंच में भी सुनवाई करेंगे। जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में वर्ष 2019 से लंबित रिट याचिका सर्विस से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई होगी। जस्टिस रजनी दुबे के सिंगल बेंच में वर्ष 2013 से लंबित क्रिमिनल रिटिवजन, ट्रांसपर याचिका क्रिमिनल, क्रिमिनल रिपैरेंस से संबंधित याचिका की सुनवाई होगी। जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में एसआरपीसी की धारा 438 के तहत जमानत आवेदन, वर्ष 2017 से लंबित रिट याचिका की सुनवाई होगी। जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में वर्ष 2018 से लंबित रिट याचिका सर्विस, सभी रिट याचिका की सुनवाई होगी।

मेकाज झेल रहा स्टाफ की कमी, कर्मचारियों में रोष

तीन दिन तीन घंटे कार्य बहिष्कार का एलान

जगदलपुर। मेडिकल कॉलेज डिम्परापाल में स्टाफ नर्स की कमी को लेकर छत्तीसगढ़ परिचरिका कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा 3 दिनों तक रोजाना 3 घंटे तक काम को बंद करते हुए रोष व्यक्त किया जाएगा। इस मामले को लेकर संघ के द्वारा संयुक्त संचालक सह अधीक्षक शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं।

छत्तीसगढ़ परिचरिका कर्मचारी कल्याण संघ के उप प्रांताध्यक्ष अनशिला बेंस ने बताया कि 13 जून से 15 जून तक रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर एक बजे तक काम को बंद किया जाएगा। अगर जल्द ही मांग को पूरी नहीं किया जाएगा तो संघ को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

संघ के सदस्यों ने यह भी बताया कि डिम्परापाल में निरंतर स्टाफ की कमी एक बड़ा रूप ले चुकी है। जिसकी वजह से स्टाफ नर्स को अपनी क्षमता से अधिक काम करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से शारीरिक व मानसिक रूप से ग्रसित हो रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो स्टाफ की कमी को लेकर कई बड़े अधिकारियों के पास मामले की जानकारी देने के बाद भी कोई भी परिणाम सामने नहीं आया है। कुछ स्टाफ नर्स ने नाम न छापने की शर्त में बताया कि हमारे यहां एकता की कमी है, जिसके कारण कोई भी खुलकर विरोध नहीं कर पाता है, अगर आधे से ज्यादा लोग हड़ताल करते भी हैं तो बाकी के लोग अपने वार्ड में ड्यूटी करते नजर भी आते हैं।

स्टाफ नर्स ने यह भी बताया कि वार्ड में ज्यादा स्टाफ होने के कारण महीने में एक बार नाइट ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन लगातार स्टाफ नर्स के तबादले, नियमित होने व अन्य कारणों के चलते कई



स्टाफ कम हो गए हैं। जिसके कारण अकेले की ही ड्यूटी लगाई जाती है।

स्टाफ नर्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक वार्ड में बिस्तर भले ही 30 रहते हैं, लेकिन वहां पर क्षमता से अधिक मरीजों को भर्ती किया जाता है। ऐसे में अकेले स्टाफ नर्स को डॉक्टर को राउंड कराने से लेकर मरीजों को इंजेक्शन, से लेकर अन्य इलाजों के लिए अकेले ही देखना पड़ता है।

बताया जा रहा है कि इस मेडिकल कॉलेज डिम्परापाल में देखा जाए तो 100 से अधिक नियमित स्टाफ नर्स कार्यरत हैं। लेकिन हक की लड़ाई में इसमें भी संख्या में कमी देखने को मिलने वाली है। जिसके कारण अधिकारी तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पावे व वार्ड में समस्या नहीं हो पाने के कारण इनके अधिकारों के ऊपर अधिकारी ध्यान नहीं दे पाते हैं।

मेडिकल कॉलेज डिम्परापाल 2018 में शुरू किया गया था। उस समय भाजपा का शासन काल चल रहा था। उस समय से लेकर अब कांग्रेस के शासन काल तक जब भी मुख्यमंत्री से लेकर अन्य मंत्री बस्तर दौरे पर आए हैं। तब तक स्टाफ नर्स को भर्ती को लेकर ज्ञान भी सौंपा गया, इस बदले उन्हें आश्वासन तो मिला लेकिन स्टाफ की पूर्ति आज तक नहीं हो पाई है। जिसके कारण लगातार स्टाफ नर्स बढ़ते कार्य के लगातार बीमार हो रहे हैं।

कांग्रेस में बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती को लेकर हुई चर्चा

कांग्रेस के अमलीडीह जोन में कार्यकर्ता सम्मेलन

धमतरी। विधानसभा धमतरी के अंतर्गत कांग्रेस के अमलीडीह जोन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया जहां अजुनी, खपरी, भानपुरी, तरसिंवा, रांवा, भोथीपार, कुरी, मड़ाईभाटा, अमलीडीह, मोखा, बगतलाई के कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए यह बैठक ग्राम भोथीपार में आयोजित हुई जहां विशेष रूप से जिला कांग्रेस कमेट्री के अध्यक्ष शरद लोहाना, दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मोहन लालवानी, कृषि उपाय मंडी के अध्यक्ष ओंकार साहू, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष घनश्याम साहू, पूर्व जनपद अध्यक्ष गुंजा साहू उपस्थित रहे। बैठक में सर्वप्रथम अमलीडीह जोन कांग्रेस संगठन की मजबूती के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए अमलीडीह जोन कांग्रेस कमेट्री का पुनर्गठन हुआ जिसमें नीलमणि साहू को जोन अध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार तरसिंवा सेक्टर अध्यक्ष नरसिंग साहू और भानपुरी सेक्टर अध्यक्ष शत्रुघन साहू को सर्वसम्मति से नियुक्त



किया गया। पूर्व में जोन एवं तरसिंवा सेक्टर अध्यक्ष परमेश्वर गिरी गोस्वामी व भानपुरी सेक्टर अध्यक्ष पुनीत राम साहू थे। सेक्टर जोन पुनर्गठन की प्रक्रिया के पश्चात् 19 बूथ कांग्रेस कमेट्री का समीक्षा किया गया जहां आवश्यकतानुसार बूथ में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। जिला कांग्रेस कमेट्री को संबोधित करते हुए कहा की सरकार की योजनाओं और उनके जनकल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है इसीलिए हम सभी का पहला दायित्व है कि हम अपने बूथ कमेट्री को मजबूत करें बूथ स्तर

के कार्यकर्ताओं का ही मेहनत है कि आज 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार है। विधानसभा में 75 सीट से अधिक कि लक्ष्य को हासिल करने के साथ-साथ धमतरी विधानसभा में विजय प्राप्त करने में बूथ अध्यक्षों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मोहन लालवानी ने कहा कि धमतरी विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने हमेशा से ही कांग्रेस को मजबूती प्रदान की है आगामी विधानसभा चुनाव में आप सभी के मेहनत और लगन से धमतरी विधानसभा की सीट जीतकर प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने हम सभी कार्यकर्ता सहयोग करेंगे। ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष घनश्याम साहू ने किसानों एवं ग्रामीण अंचल के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को किसानों को कांग्रेस पार्टी में जोड़ने अपील किया गया। कार्यक्रम का आभार जोन कांग्रेस कमेट्री के अध्यक्ष नीलमणि साहू एवं संचालन पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुरु गोपाल गोस्वामी के द्वारा किया।

रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर की ओपीडी अब भिलाई में भी

मल्टीस्पेशलिटी भिलाई सिटी क्लीनिक में आज से शुरुआत

भिलाई। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर की ओपीडी जैसी नियमित सेवाएं अब रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल ओर से भिलाई के मल्टीस्पेशलिटी भिलाई सिटी क्लीनिक में 11 जून, रविवार से प्रारंभ हो रही है। सी-70, नैदिनी रोड, जैन मेडिकल और सर्जिकल के पास, पावर हाउस, भिलाई में विधिवत शुभारंभ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के मैनेजिंग व मेडिकल डायरेक्टर डॉ. संदीप दवे करेंगे।

मल्टीस्पेशलिटी भिलाई सिटी क्लीनिक में विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप पांडे, डीएम गेस्ट्रोइंटरीलाजी, डॉ. देबा दुलाल बिस्वाल, मेडिकल आकोलाजी, डॉ. गिरीश अग्रवाल, पेलमोनोलॉजिस्ट, डॉ. सुमन नाग, एमएस आर्थो, आर्थोस्कोपी जै, स्पोर्ट्स इंचुरी, डॉ. प्रणय अनिल जैन, डीएम कार्डियोलॉजी, डॉ. जावेद परवेज, डीएम

कार्डियोलॉजी, डॉ. राहुल पाठक, डीएम न्यूरोलाजी, डॉ. अंकुर सिंघल, एमएस आर्थो, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, डॉ. बबलेश महावर, पेन डॉ. पेलेटिव केयर, डॉ. उज्ज्वला वर्मा, एमडी (डीवीएल) हरमेटोलॉजिस्ट व डॉ. नमन जैन रुमेटोलॉजिस्ट जांच व परामर्श हेतु सप्ताह में अलग-अलग दिन उपलब्ध रहेंगे। पंजीयन के लिए 9685455735 9755595859 पर संपर्क किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत में विश्वस्तरीय चिकित्सा व सर्जरी की अत्याधुनिक सुविधाओं के लिये प्रतिष्ठित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल की चिकित्सकीय सेवाएं लगातार विस्तारित की जा रही हैं। हृदय रोग, किडनी, लिंवर, मस्तिष्क संबंधी जटिल से जटिल रोगों के मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज, यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों व कुशल अनुभवी स्टाफ के द्वारा होता है। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. संदीप दवे हैं।

कांग्रेस नेता पीला राम नेताम समेत 300 से अधिक लोगों ने भाजपा प्रवेश किया

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लामार्थी सम्मेलन में नगरी पहुंचे

नगरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफ्त कार्यकाल 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है जिसको लेकर शुक्रवार को नगरी के गाँधी चौक (राजबाड़ा) में सिहावा विधानसभा के केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले विशाल लामार्थी सम्मेलन सम्बोधित करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव नगरी पहुंचे। नगरी पहुंचने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर प्रदेश अध्यक्ष श्री साव नगर प्रवेश करवाया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साव ने कहा कि मोदी सरकार बनाएगी सभी गरीबों के लिए पक्का मकान, गरीब को इलाज के लिए घर का बर्तन जेवर, बेचना नहीं

पड़ेगा। भाजपा गांव, गरीब, किसानों के लिए समर्पित पार्टी है नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बेटीयों, महत्तरिओं को रात को घर से बाहर ना निकलना पड़े, इसलिए घर-घर शौचालय बनाया गया। लकड़ी चूल्हा जलाने से होने वाली बीमारीयों से बचाने के लिए मुक्त रसोई गैस दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रत्येक किसान को 6000 रु दे रहे। गरीबों के बैंक खाते खोले गए। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत पांच लाख तक के स्वास्थ्य लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। करोना काल में टीकाकरण के

अलावा, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल मुक्त दिया गया। आज विभिन्न योजनाओं से छत्तीसगढ़ के आम लोगों को लाभ पहुंचा रही है जिसमें प्रमुख रूप से आवास योजना जिसमें हर गरीब को पक्की मकान मिले मगर

प्रेमलता नागतंशी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भव्य स्वागत

बोरई पहुंचे भाजपा



प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव व बस्तर महाराजा कमल चंद्र भंजदेव का भव्य स्वागत सत्कार भाजपा जिला मंत्री एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमलता नागतंशी के नेतृत्व में किया गया। बता दे कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सड़क मार्ग से बस्तर से सिहावा के प्रवेश द्वार बोरई होते हुए नगरी राजबाड़ा में 9 साल सेवा सुश्रुतन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत लामार्थी सम्मेलन में शामिल होने जा रहे थे। वहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत के पश्चात् प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कार्यकर्ताओं को उद्बोधन भी दिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ बस्तर महाराजा कमल चंद्र भंजदेव, जिला सह प्रभारी हलधर साहू, राष्ट्रीय मंत्री पिंकी शाह, पूर्व विधायक श्रवण मरकाम, जिला मंत्री प्रेमलता नागतंशी, मंडल अध्यक्ष अमर करश्यप, मंडल

छत्तीसगढ़ की भूपेश की कांग्रेस सरकार आवास योजना को छत्तीसगढ़ में बंद कर गरीबों का हक छीनने का काम किया केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा को भूपेश बघेल नरवा चुरवा बाड़ी में लगाकर गौठान के

आड़ में बहुत बड़ा प्रयाचार का खेल खेल रहा है जिसको छत्तीसगढ़ वासी और सिहावा विधानसभा के मतदाता समझ गए आने वाले चंद महीनों में चुनाव होंगे जिसमें कांग्रेस को मतदाता सबक सिखाएगी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पीला राम नेताम सहित 300 से अधिक लोगों ने भाजपा प्रवेश किया।

इस दौरान मंच पर कांगेर लोकसभा के सांवत मोहन मंडावी, पूर्व केबिनेट मंत्री चन्द्रशेखर साहू, जिला प्रभारी नीलू शर्मा, विधानसभा प्रभारी कमल चंद्र भंजदेव, जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार, राष्ट्रीय मंत्री किसान मोर्चा पिंकी शिवराज शाह, पूर्व विधायक श्रवण मरकाम, हलधर साहू कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री प्रकाश बैस ने किया।

